जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/jk/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 3 अप्रैल 2020

रोटी या राजनीति?

आखिर कौन है यह 5000 गुमनाम लोग,जिनका पेट हमारे विधायक महोदय सरकारी पैसे से भरना चाहते है?

फूड सप्लाई पर अफसर और जनप्रतिनिधि आमने-सामने

विधायक: एक-एक करोड़ दिए फिर भी 12 हजार घरों में ही पहुंचे
प्रशासन: हम सर्वे के हिसाब से जरूरतमंदों को दे रहे सामग्री

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

आदर्शनगर विधायक ने कलक्ट्रेट में अधिकारियों पर उठाए सवाल, कहा– 11 दिन लॉकडाउन के बाद भी जयपुर में अधिकारी नहीं सभांल पा रहे खाद्य सामग्री व्यवस्था

जयपुर. लॉकडाउन के दौरान शहर में वितरित की जा रही सूखी खाद्य सामग्री पर अब अफसर और जनप्रतिनिधि आमने-सामने हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि जहां अपने क्षेत्र में सामग्री वितरण नहीं होने पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं प्रशासन सर्वे के आधार पर जरूरमतंदों को ही सामग्री बांटने की बात कह रहा है।

गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचे आदर्शनगर विधायक रफीक खान ने एडीएम सहित वितरण व्यवस्था में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधायकों के कोष से एक–एक करोड़ रुपए देने के बाद भी शहर में अभी तक महज 12 हजार फूड पैकेट्स ही बांटे गए हैं। इस हिसाब से एक विधानसभा में अभी तक एक हजार पैकेट भी पूरे नहीं बंटे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 11 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पूरे शहर में जरूरतमंदों के पास भोजन सामग्री पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिला प्रशासन वितरण व्यवस्था में फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं है तो सरकार को डिमांड क्यों नहीं भेजी जा रही हैं।

कलक्ट्रेट में विधायक के विरोध के दौरान आदर्श नगर में वितरित की गई सूखी सामग्री के दस्तावेजों को सिविल डिफेंस की टीम ने विधायक को दिखाए।

जो सूची मैंने सौंपी एक के पास भी नहीं पहुंचा पैकेट

विधायक खान ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के करीब पांच हजार से अधिक लोगों की सूची मैंने सौंपी हैं। उनके पास ना राशन कार्ड है ना ही खाद्य सुरक्षा सूची में नाम। ऐसे में उनके खाने का संकट पैदा हो रहा है। प्रशासन को सूची सौंपने के बाद भी खाना नहीं बंटा जा रहा है। उन्होंने सिविल डिफेंस से कराई जा रही वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि राशन कार्ड होल्डरों को भी पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं।

आरोप के बाद रोने लगे चीफ कंट्रोलर बोले

कम से कम वेतन में नेताओं के दबाव में काम कैसे करें

सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक जगदीश रावत विधायक के आरोप के बाद रोने लग गए। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा का सदस्य कम वेतन में आपातकाल में सेवा दे रहा है। शहर में फूड सप्लाई कर रहा हैं। ऐसे में आरोप सही नहीं हैं। हमने सर्वे करवाया हैं। सर्वे के मुताबिक ही जरूरतमंदों को सामग्री पहुंचा रहे हैं। हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों की सूची आ रही हैं। ऐसे में दबाव में काम कैसे करेंगे। हम जनता के बीच जाकर जरूरतमंदों को पैकेट रहे हैं, सभी से हस्ताक्षर ले रहे हैं। प्रशासन चाहे तो जांच करवा सकता है।

क्या है ड्राई फूड सप्लाई में

5 किग्रा आटा, 1/2 लीटर खाद्य तेल, 1/2 किग्रा नमक, 1 किग्रा दाल और 1 किग्रा चावल की खाद्य सामग्री (ड्राई राशन) निःशुल्क दिए जाने का दावा किया गया है।

सरकार के निर्देश है कि सत्यापन के आधार पर ही चयनित लोगों को सूखी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की ओर से आ रही सूची का भी सत्यापन कराया जा रहा है।

जोगाराम, कलक्टर जयपुर

इस खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद

दिनांक 03/04/2020 को प्रकाशित खबर

रोटी या राजनीति?

आखिर वही हुआ जिसका डर था,जहाँ एक और कोरोना ने आम जन,सरकार को परेशान कर रखा है वहीं दूसरी और राजनीति के नाम पर अपने मतलब की रोटियां सेकने वाले नेताओं की गतिविधियाँ भी तेज हो गयी है| जनता को राहत देने के नाम पर जन प्रतिनिधियों और प्रशासन में टकराव होने लगा है|इसी क्रम में हमारे आदर्शनगर के विधायक महोदय प्रशासन पर दबाव बना रहे है है कि वह उनके द्वारा सौपी गयी 5000 लोगो की सूची के अनुसार राहत कार्य करवाए|उनके अनुसार यह वह लोग है जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही खाद्य सुरक्षा सूची में नाम|जबकि प्रशासन का कहना है कि सत्यापन के बाद ही चयनित लोगो को राहत उपलब्ध करवाई जाएगी|ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है|

जवाब मांगते सवाल?

1. विधायक महोदय द्वारा जिन 5000 लोगो की सूची प्रशासन को उपलब्ध करवाई गयी है,आखिर वो कौन लोग है?क्यों उनके पास राशनकार्ड या उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है?
2. क्या कारण रहे है कि इन लोगो ने आज तक राशनकार्ड नहीं बनवाए है या अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में दर्ज नहीं करवाया है?
3. कहीं यह बाहरी लोग घुसपैठिये/बांग्लादेशी/रोहिंग्या तो नहीं है?
4. इस सूची में कितने व्यक्ति धर्म विशेष के है?
5. यह सूची तो केवल एक विधानसभा क्षेत्र की है ऐसी ही सूची जयपुर परकोटे के अन्य विधायकों द्वारा भी सौपी गयी है,आखिर शहर में कितने ऐसे अवैध लोग ठहरे हुए है जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है?

6. यदि विधायक कोष के धन से ख़रीदा गया राशन इन लोगो को उपलब्ध करवाया जायेगा तो क्या यह उन लोगो के हितों पर आघात नहीं होगा जिनके पास राशनकार्ड उपलब्ध है या जिनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची में दर्ज है?
7. विधायक महोदय प्रशासन को इस सूची का सत्यापन क्यों नहीं करने दे रहे है और क्यों प्रशासन पर अनुचित दबाव बना रहे है?
8. विधायक महोदय का दबाव उचित है या अनुचित? क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी?
9. क्या विधायक महोदय के इस उचित/अनुचित दबाव से इस संकट के समय में दिन-रात काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल नहीं गिरेगा?